*17 वाँ सी.डी.देशमुख स्मारक व्याख्यान: उद्घाटन उद्बोधन**

शक्तिकांत दास

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से मैं श्री ऑगस्टिन कर्स्टेन्स (Mr. Agustin Carstens), महाप्रबंधक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेट्टलमेंट्स का सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यानमाला में आज 17वाँ व्याख्यान देने के लिए सहर्ष स्वागत करता हूँ। हम आज स्व.सी.डी.देशमुख के परिवार के श्री अतुल देशमुख एवं श्रीमती देशमुख को भी अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत है।

आरंभ में, मैं इस अवसर पर श्री सी.डी.देशमुख को याद करते हुए उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। श्री चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख का जन्म 14 जनवरी 1896 को महाराष्ट्र में रायगढ़ फोर्ट के निकट नाटा में हुआ था। उनका शैक्षणिक करियर अप्रतिम था। उन्होंने 1912 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 1917 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जीसस कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1918 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, जो उस समय केवल लंदन में आयोजित होती थी, में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1920 में भारत वापस लौटने पर उन्होंने बिहार सरकार और भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ उनका संबंध जुलाई 1939 में आरंभ हुआ जब उन्हें बैंक के मामलों के संदर्भ में भारत सरकार से संपर्क बनाए रखने के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तीन महीने बाद उन्हें बैंक के केंद्रीय बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया और दो वर्ष बाद दिसंबर 1941 में उनको बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। 11 अगस्त 1949 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाले वे प्रथम भारतीय थे और वे 30 जून 1949 तक इस पद पर सुशोभित रहे। उन्होंने औद्योगिक वित्त निगम बनाए जाने और ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभायी। अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 बनते हुए देखा जिसने भारत में बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन की आधारशिला रखी। उनके कार्यकाल के दौरान ही भारतीय रिज़र्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ।

श्री देशमुख भारतीय रिज़र्व बैंक में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद योजना आयोग के सदस्य बने जब योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। इसके बाद वे 1950 में वित्त मंत्री बनाए गए और जुलाई 1956 तक देश को अपनी विशिष्ट सेवा प्रदान की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश की प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वे नये कंपनी अधिनियम बनाए जाने और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया तथा जीवन बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख कारक थे। केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद वे उन्होंने 1956 से 1961 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष और 1962 से 1967 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। 1975 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। विशिष्ट सरकारी सेवा के लिए 1959 में दिए गए प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार के भी वे सह विजेता रहे।

श्री सी.डी.देशमुख के सम्मान में इस वर्ष के स्मारक व्याख्यान में श्री ऑगस्टिन कर्स्टेन्स को अपने बीच पाकर हमें अत्यंत प्रसन्नता है। ये 2010 से 2017 तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ मेक्सिको के गवर्नर रहे और 2011 से 2017 तक बीआईएस बोर्ड के सदस्य रहे। बीआईएस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने वैश्विक आर्थिक बैठकों और आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठकों की अध्यक्षता की। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की परामर्शदात्री समिति अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (इंटरनेशनल मॉनेटरी ऐंड फायनान्शियल कमिटी) की भी अध्यक्षता की।

श्री कर्स्टेन्स ने अपने करियर की शुरुआत 1980 में बैंक ऑफ मेक्सिको से की जहाँ इन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। बाद में इन्होंने मेक्सिको के उप वित्त मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा प्रदान की। ये 2006 से 2009 तक मेक्सिको के वित्तमंत्री रहे।

ये 2010 तक वित्तीय स्थिरता बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं तथा समूह 30 (ग्रुप ऑफ थर्टी) के सदस्य हैं।

श्री कर्स्टेन्स ने शिकागो यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है तथा इन्हें मैक्रोइकोनॉमिक मुद्दों

* 25 अप्रैल 2019 को मुंबई में सत्राहवें सी. डी. देशमुख मेमोरियल व्याख्यान में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए उदघाटन उद्बोधन।

और वित्त के क्षेत्र में गहन शोध का अनुभव है। 'लैटिन अमेरिकन सेन्ट्रल बैंक रिफॉर्म : प्रोग्रेस ऐंड चैलेंजेज ' पर किया गया उनका कार्य जो लैटिन अमेरिका में मौद्रिक नीति में 1990 के आरंभिक वर्षों से किए गए संस्थागत सुधारों का जायजा लेता है, की व्यापक स्तर पर सराहना हुई।

आज श्री कर्स्टेन्स "Central Banking and Innovation : Partners in Quest for Financial Inclusion" विषय पर बोलेंगे जो आज की परिस्थिति में अत्यंत प्रासंगिक विषय हो सकता है। हाल ही में वित्त के क्षेत्र में उभर कर सामने आए फिनटेक अथवा डिज़िटल नवाचार वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र को आकार देने की दिशा में संभावनाओं से भरी एक मजबूत रूपांतरणकारी शक्ति बन गए हैं। इस प्रौद्योगिकीगत विकास का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे वहनीय लागत पर वित्तीय पहुँच के विस्तार की गुंजाइश बढ़ी है। लेकिन इसके साथ ही विनियामक और पर्यवेक्षी चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं जिनको वैश्विक स्तर पर सभी केंद्रीय बैंकों द्वारा ठीक किए जाने की जरूरत है।

रिज़र्व बैंक भारत में वित्तीय समावेशन अभियान को बढ़ावा देने तथा इसकी गति तेज़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में फिनटेक में हुए विकास ने देश में वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को एक नयी गति दी है। भारत में डिज़िटाइजेशन की आई तीव्र वृद्धि और ऑनलाइन व्यापार का संज्ञान लेते हुए हाल के दिनों में एक नवोन्नत राष्ट्रीय भुगतान आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनाए जाने की दिशा में नीतिगत प्रयास किए गए हैं। रिज़र्व बैंक अपने विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे को निरंतर एक दूसरे के अनुकूल बना रहा है ताकि वंचित जनसामान्य तक वित्तीय पहुँच को विस्तार देने और उसे आसान बनाने में मदद देने के लिए फिनटेक के विकास को और सशक्त बनया जा सके। फिनटेक नवाचारों के बढ़ते महत्व और वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के साथ उसके अंतर्संबंधों की दृष्टि से रिज़र्व बैंक अपने निगरानी ढाँचे को मजबूत कर रहा है तथा बैंक द्वारा हितधारकों से अभिमत प्राप्त करने के लिए "Enabling Framework for Regulatory Sandbox" पर दिशानिर्देश का प्रारूप भी जारी किया गया है। आज श्री कर्स्टेन्स के वक्तव्य से हमें इस दिशा में निश्चित रूप से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होगी।

मैं श्री कर्स्टेन्स को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ।